

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....



जवाब दो!!! सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -20119/MMP/13

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 18 सितम्बर 2019



जे.डी.सी. महोदय, अपने पुलिस जासे को वापस लाईन में भेज दीजिये! क्यूंकि यह ना तो अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही करेंगे और ना ही अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स, बिना अनुमति आवासीय परिसरों में चल रही शराब की दुकानों, होटलों, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर।

जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा में पूरा जासा! फिर भी ना रामगढ़ भरा ना ही शहर से अवैध निर्माण हट रहे।

जे.डी.ए. में बहुत समय बाद पर्याप्त पुलिस जासा तैनात है इस समय जे.डी.ए. में एक पुलिस अधीक्षक, एक अति. पुलिस अधीक्षक, दो उप पुलिस अधीक्षक व 13 इंस्पेक्टर तैनात है, परन्तु बावजूद इसके शहर अवैध निर्माणों से बदरंग होता जा रहा है। यदि आप प्रवर्तन शाखा जायेंगे तो आपको वहां कोई इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा, पूछने पर पता चलेगा कि वह तो रामगढ़ खाली करवाने गए है, ईधर शहर में हो रहे अंधाधुंध अवैध निर्माणों से आम आदमी परेशान है और न्याय के लिए हर स्तर पर चक्कर लगाने को मजबूर है।



प्रवर्तन शाखा की अमीरों से दोस्ती, गरीबों से दुश्मनी।

जे.डी.ए. का प्रवर्तन विभाग दिखावे के लिए केवल गरीबों की बस्तियों को उजाड़ कर ही अपनी पीठ थपथपाता रहता है, भू-माफियाओं, बिल्डरों के मामले आने पर यहाँ तैनात इंस्पेक्टरों के मुंह में पानी आ जाता है और तुरंत मामला सेट करने में नहीं हिचकते।

अवैध कोचिंग और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को सील करने पर चुप्पी साधी।

सूरत अग्रिकांड के बाद जे.डी.ए. ने आनन फानन से टीमें बनाते हुए 250 से अधिक कोचिंग संस्थानों और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को सील करने का नोटिस थमा दिए, अखबारों में बड़ी-बड़ी बातें छपी, इन अवैध कोचिंग, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स चलाने वालों की यूनियनों से अलग-अलग मीटिंग्स की परन्तु ढाक के तीन पात; नोटिस देने के 20 दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं।

जेडीए के बाहर कई बिल्डर्स ने निकाला पैदल मार्च

अवैध निर्माण कर बोले अब हटा लेंगे

जेडीए ने शहर के अन्य इलाकों में भी अवैध निर्माण किए बिन्दित



जेडीए के बाहर प्रवर्तन करते बिल्डर्स।

जेडीए ने अवैध निर्माणों की सूची मांगी

जेडीए के आवास वरिष्ठ अफसर सिंह, एचएच प्रिंसिपल और प्रवर्तन शाखा के मुख्य निरीक्षक राहुल सेठी के साथ प्रिंसिपल और वरिष्ठ अफसर अजय शर्मा के साथ बैठक हुई।

प्रिंसिपल अफसर ने कहा- जो निर्माण हो गए, उन्हें छोड़ दें। आगे से हर निर्माण निर्माणों के अनुमति पत्रों के बिना नहीं होगा।

जेडीए- ऐसा नहीं होगा। कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रिंसिपल अफसर - अवैध निर्माणों को हटा दें, तब हम खुद ही हटा लेंगे।

जेडीए- एक ही दिन में जेडीए को अवैध निर्माणों की लिस्ट दी जाए और जब तक अवैध निर्माण हटते, तो हमें कार्रवाई करना पड़ेगी।

इन पर भी हुई चर्चा

■ निर्माणों में सरकारीकरण किया जाए।

■ निर्माण विभाग विभागीय अधिकारियों को अवैधों में मुहर लगाकर काम कर रहे हैं। उदा, जेडीए की ओर से कई जगहों पर अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। जेडीए की ओर से कहा गया है कि इन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को नहीं हटाया जाए, जो जेडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

कई बार रोका, फिर भी खड़ी हो गई इमारत

पुणेवाले नगर के बाजारों नगर में दो पुरानी को निर्माण करने पर इमारत को जेडीए जैन उद्योगिक विकास एकाईजमेंट डिवीज, पुणेवाले प्रवर्तन शाखा के मुख्य निरीक्षक राहुल सेठी ने रोका किया गया है। उन्होंने बताया कि पुरानी नगर की इमारत को विचारवादी हटाने से आ रही थी। रोकने के बाद भी जैन उद्योगिक विकास निर्माण हो गया। इमारत को निर्माणकर्ता ने नगर पंचायत को हटाने की बात कही।

लापरवाही एक इंस्पेक्टर और दो कार्टेबल को किया रिलीव

नगर निगम की सर्वेक्षण शाखा के इंस्पेक्टर को एक बड़ा इन्फेक्टर और दो कार्टेबल को रिलीव कर दिया। दोनों पर निर्माण के करने को रोके का आरोप है। दोनों ने खंड नगर में न सिर्फ निर्माण कराया, बल्कि एक के बाद एक घर बनाने भी कराया है, जिससे नगर के उपकरण एकाईजमेंट डिवीज को रिलीव कर दिया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्रवाई का इन्फेक्टर नगर, कार्टेबल पंचायत और निगम पर आरोपों को कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। नगर निगम के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि निर्माणकर्ता को रिलीव करने के निर्देश दिए। पुराने टैक्स नोटों में यह निर्देश दिया।

निर्माण के विवाद ही रहे निर्माण रोकने नहीं किए जाएंगे। जेडीए/प्रिंसिपल ने अवैध निर्माणों में निर्माणों के अनुमति पत्रों को रिलीव कर दिया। निर्माण कार्रवाई को रोकना नगर को रोका नहीं।

टी रिकॉर्ड, जेडीए निर्माणों में हो सरलीकरण

कुछमात्र को कुछ 10 करोड़ टैक्स निर्माणों के साथ केवल है। इन्होंने निर्माणों को रोकने का निर्देश नहीं दिया। जेडीए और प्रिंसिपल ने, जेडीए के अनुमति पत्रों को रिलीव कर दिया।

जोन	अवैध बिल्डिंग
07	50
08	24
09	23
13	14
14	14
15	20
16	20

अवैध रूप से फ्लेट बनाने वाले भी पहुंचे हल्ला करने।

जे.डी.ए. प्रवर्तन ने जब पृथ्वीराज ज़ोन में बिना अनुमति, बिना नक्शे अनुमोदित करवाने और अन्य भवन विनियमों का उल्लंघन करने पर अवैध बिल्डिंगों पर कार्यवाही शुरू की तो अवैध निर्माणकर्ता भी एसोसिएशन बना कर कार्यवाही रोकवाने जे.डी.ए. पहुँच गए, जिसके चलते इन अवैध निर्माणों पर भी कार्यवाही रोक दी गयी है।

एसोसिएशन से मीटिंग; समझाईश या डील??

आजकल जे.डी.ए. में नया ट्रेंड चल रहा है पहले तो नियम विरुद्ध निर्माण करें, राजस्व को नुकसान पहुंचाओं फिर यदि जे.डी.ए. कार्यवाही करें तो कार्यवाही रोकवाने के लिए एसोसिएशन बनाओ, किसी मंत्री/नेता को उसका संरक्षक बनाओ और पहुंच जाओ जे.डी.ए. में मीटिंग करने। पिछले कुछ महीनों में यह ट्रेंड खूब दिखाई दे रहा है। चाहे वो कोचिंग एसोसिएशन हो या फिर रूफ टॉप मालिकों, छोटे बिल्डरों की एसोसिएशन सब यही हथकंडा अपना रहे

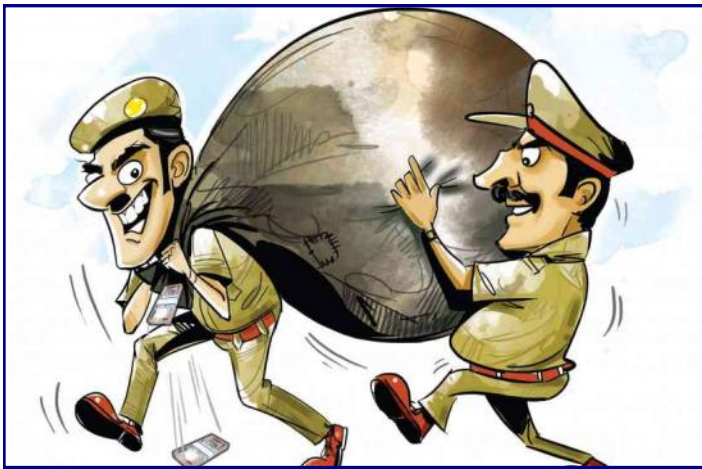
आवासीय परिसरों में चल रही शराब की दुकानों को कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग भेज रहे है चिट्ठी

शहर में एक नहीं सेकड़ों की तादात में बिना अनुमति आवासीय परिसरों में शराब की दुकाने संचालित की जा रही है जिनका आये दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन होता है परन्तु जे.डी.ए. ऐसे मामलों पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर उल्टा कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग को चिट्ठियां लिख रहा है।

आवासीय परिसरों में चल रही होटलों/डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने के लिए नीतिगत फैसला

शहर में आ रही शिकायतों में एक और समस्या आवासीय परिसरों में चलने वाली होटलों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की है, जिन पर भी प्रवर्तन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर, नीतिगत फैसला बता कर पल्ला झाड़ा जा रहा है।

है, जिससे बातचीत के नाम पर या तो दबाव बनाया जाता है या फिर होती है कोई मोटी डील।



शराब की दुकाने, होटले, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि को हटाने के लिए नीतिगत फैसले, पता नहीं कौन कब लेगा?

शहर में जगह जगह आवासीय परिसरों में शराब की दुकाने, होटले और डिपार्टमेंटल स्टोर्स व अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है, जिनकी लगातार शिकायतें प्रवर्तन शाखा को प्राप्त हो रही है परन्तु जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा इनको सील करने की बजाय यह मामला नीतिगत बता कर कोई कार्यवाही करने से मना कर देती है और शिकायत को बंद कर देती है। अब पता नहीं यह नीतिगत फैसला कौन और कब लेगा जिससे शहर को अवैध निर्माणों से राहत मिलेगी?

जेडीसी ने अफसरों से पूछा 'कोई ऐसा काम बताओ, जो जनता के हित में किया हो'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए में सोमवार को प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के साथ जेडीसी टी. रविक्रान्त ने बैठक की। इसमें उन्होंने नियम विपरीत बन रही तिर्मांजिला इमारतों पर कार्रवाई करने, सुविधा क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।

बैठक में जोन वार समीक्षा में उन्होंने प्रवर्तन शाखा के अफसरों से पूछा कि ऐसा काम बताओ जो जनता के हित में किया हो। इस पर किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। जेडीसी ने कहा कि जनहित को प्राथमिकता देनी होगी। बैठक में सचिव अर्चना सिंह, निदेशक

रामगढ़ बांध

जेडीसी ने कहा कि चार टीमें बनाएं और रोज कार्रवाई करें। अतिक्रमण हटाने में भेदवाद न हो।

पार्किंग

जेडीसी ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा दी गई पार्किंग स्थलों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त करें। अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों के सामने से अवैध पार्किंग स्थल हटाएं। गाड़ियां रोड पर खड़ी हों तो संबंधितों को नोटिस जारी करें।

(आयोजना) आरसी विजयवर्गीय, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, वरिष्ठ नगर नियोजक ओपी पारीक, जोन उपायुक्त मौजूद थे।

प्रवर्तन शाखा में भ्रष्टाचार चरम पर

जे.डी.ए. में अवैध निर्माणों की शिकायतों का ही नहीं एक और चीज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो है भ्रष्टाचार जिससे आहत होकर मंत्री श्री शांति धारिवाल को जे.डी.ए. अधिकारियों को बुला कर डांट लगानी पड़ी। जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कभी कलेक्टर के नाम से, कभी प्रवर्तन अधिकारी का ड्राईवर तो कभी खुद प्रवर्तन अधिकारी को अवैध निर्माण करवाने/रुकवाने की डील करते पकड़ा जा चुका है, परन्तु जे.डी.ए. के बड़े अधिकारी इन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर इन्हें बचा रहे हैं। ऐसे में जे.डी.सी. भी कई मौकों पर प्रवर्तन दस्ते से पूछ चुके हैं कि कोई ऐसा काम बताओं जो आप लोगो ने जन हित में किया गया हो?

जब प्रवर्तन शाखा को काम ही नहीं करना है तो इतने पुलिस जासे का बोझ क्यों?

अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रवर्तन की ढीली चाल को देखकर लगता है कि जब इस विभाग को काम ही नहीं करना है तो क्यों जनता पर इनकी तनख्वाह, गाडी-घोड़ो, जेसीबी आदि भारी लवाजमों

का खर्चा लाद रखा है, इससे बढ़िया तो इनको वापस पुलिस लाईन ही भेज दिया जाए ताकि शहर में अमन शांति तो बनी रहे।

शिकायतों में पक्षपात पर जेडीए डिप्टी कमिश्नर और प्रवर्तन अधिकारी हटाए

वैशाली नगर में एक होटल व मल्टीस्टोरी को नोटिस देने के बाद उपजा विवाद, अब अवैध निर्माण व अतिक्रमणों पर कार्रवाई को लेकर कंप्यूजन के हालात

जयपुर | शहर में अवैध निर्माण व अतिक्रमणों की शिकायतों के मामले में प्रवर्तन विंग और जोन विंग के अफसरों की मिलीभगत व भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोपों के बाद पहली बार सरकार ने जेडीए जोन 7 के डिप्टी कमिश्नर संजय शर्मा और प्रवर्तन अधिकारी मुकेश कुमार को हटाकर दूसरे अफसरों को चार्ज दे दिया है। दोनों ही अधिकारियों को कोई काम नहीं दिया गया है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री व स्थानीय विधायक लालचंद कटारिया की शिकायत के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारिवाल ने शनिवार को

जेडीए की प्रवर्तन विंग के अफसरों को तलब किया था। जेडीए के एडिशनल कमिश्नर गिरीश पाराशर ने बताया कि जिन जोन का काम डीसी संजय शर्मा के पास था, उन जोन का काम दूसरे डिप्टी कमिश्नर को दिया है। इनको फिलहाल कोई काम नहीं दिया।

डिप्टी कमिश्नर संजय शर्मा के पास अब तक जोन 6, 7 और पीएनआर 16 व 17 का चार्ज था। अब जोन 6 का काम डीसी प्रिया बलराम, जोन 7 का अब सुफियान चौहान और पीएनआर 16 व 17 का काम बलवंत सिंह को चार्ज दिया है।

प्रवर्तन अधिकारी मुकेश कुमार को हटा कर जोन 6 का चार्ज जोन 13 के प्रवर्तन अधिकारी सुरेंद्र सिंह को दिया है।

जेडीए के जोन व प्रवर्तन विंग की ओर से 'पिक एंड चूज' के कॉन्सेप्ट को लेकर हो रही कार्रवाई सवालों में है। जेडीए रीजन में बिना भूरूपांतरण के गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टों पर धड़ल्ले से कॉलोनियां बसाई जा रही है। लेकिन कुछ अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और अन्य की शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करने के बजाए केवल नोटिस देकर खानापूत हो रही है।

वैशाली से फिर आई
शिकायतों पर एसपी
की मुहर, जेडीसी ने
एक और ईओ हटाया

इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर

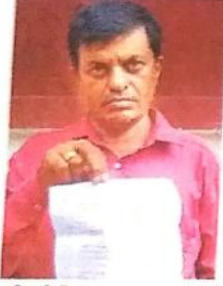
वैशाली नगर में अवैध निर्माण के मामलों में मिलीभगत और कार्रवाई के दौरान जेडीए की एनफोर्समेंट शाखा की ओर से भेदभाव के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। डेढ़ महीने पहले स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की शिकायतों पर यूडीएच मंत्री ने एक ईओ को एपीओ कराया था। इसके बाद सोमवार को एक और प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) सुरेंद्र सिंह बांगड़वा को जेडीए से बाहर का रास्ता दिखाया है। बांगड़वा पर वैशाली नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामलों पर मिली शिकायत की एडिशनल एसपी रघुवीर सैनी और एसपी प्रीति जैन की तपतीश में गड़बड़ियां पाई गईं। जेडीसी टी रविक्रान्त के सामने रिपोर्ट रखने पर उन्होंने ईओ को जेडीए से रिलीव करने को कहा। सोमवार को एसपी ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।

कहा: मकान नहीं बनाने दे रहा, कार्रवाई के लिए कई बार जेडीए की टीम भेज चुका है

19/07/18

कलक्टर से बोला फरियादी... आपके नाम से धमका रहा है कोई

कलक्टर ने ली लिखित शिकायत, जेडीए को कहा-जांच कर बताओ सच क्या है



फरियादी भेरुलाल

आश्चर्य किया कि कलक्टर से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। कलक्टर ने पीड़ित को लिखित शिकायत ली, जेडीए सचिव को पत्र भेजकर 7 दिन में कार्यवाही कर रिपोर्ट मांगी है।

यह है मामला: पीड़ित भेरुलाल ने लिखित शिकायत दी कि गौनेर रोड कालवाड़ रोड पर छरीदे प्लॉट पर डुप्लेक्स बनवा रहा हूँ। 23 जून को प्रमप्रकाश चोटिया नामक व्यक्ति ने 7976072300 नम्बर से फोन कर कहा कि मैं कलक्टर ऑफिस में बड़ा अधिकारी हूँ। तैरा मकान तुड़वा दूंगा। इस पर मैंने गांधीपथ वेशालीनगर में मिटिंग की और 50 हजार रुपए देकर राजीनामा कर लिया। लेकिन 14 जुलाई को 9772201212 नम्बर से फोन कर कहा कि मैं जयपुर

जवाब मांगते

सवाल
पीड़ित जो नाम ले रहा है, वह जिला कलक्टर के निजी सहायक सचिव हैं

पीड़ित ने जो मोबाइल नंबर दिए, वह कलक्टर के निजी सचिव के ही हैं

जेडीए की टीम कार्रवाई करने गई तो कहा कि कलक्टर से फोन आया है

कलक्टर का आदमी हूँ, दो लाख रुपए दो। इसके बाद जेडीए से जितेन्द्र सिंह नामक अधिकारी आए और कहा कि कलक्टर के यहां से फोन आ रहे हैं।

कलक्टर बोले जेडीए का मामला

इस मामले में कार्रवाई के लिए जेडीए सचिव को लिखा है। हमारे यहां से जेडीए को कार्रवाई करने के लिए फोन नहीं गया। जो भी टीम गई है, उससे पूछा जाए। सात दिन में कार्यवाही से अवगत कराने के लिए भी बोला है।

जगरूप सिंह यादव, जिला कलक्टर, जयपुर

जेडीए

हमें कंटोल रूम पर सूचना आई लेकिन शिकायत कलक्टर से आई थी। मैं मौके पर गया था। वहां जी प्लस टू पहले से बना था, वह दूसरी मंजिल बना रहा था। काम नहीं रुकवाया, जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

जितेन्द्र सिंह, प्रवर्तन अधिकारी

निजी सहायक

मुझे नहीं पता यह क्या मामला है। मेरा नम्बर शिकायत में क्यों लिखा पता नहीं। मैंने जेडीए में फोन नहीं किया। कलक्टर साहब ने मुझे बुलाकर इस बारे में पूछा मगर मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।

प्रेमचंद चोटिया, निजी सहायक, जिला कलक्टर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर, जिला कलक्टर में गुरुवार को एक व्यक्ति ऐसी शिकायत लेकर पहुंचा, जिसे सुनकर खुद कलक्टर जगरूप सिंह यादव दंग रह गए। उसने कलक्टर से कहा, आपके ऑफिस से मुझे धमका भरा फोन आता है। मुझे मकान नहीं बनाने दे रहा है। फोन पर कहता है कि मैं कलक्टर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। कार्रवाई के लिए जेडीए से बार-बार

टीम भेज रहा है। परेशान हो गया हूँ। आप ही फोन करा रहे हो क्या? कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने उक्त पीड़ित भेरुलाल अग्रवाल को

जेडीए में भ्रष्टाचार का कड़वा सच...

नियम कायदे से बन रहे मकान पर रिश्तत लेने पहुंचा ठेके का ड्राइवर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए में प्रवर्तन शाखा में ठेके पर काम करने वाले वाहन चालक भी शहर में खूब अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है।

जून-05 के प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) के चालक पवन ने गुर्जर की थड़ी में मकान बना रहे एक व्यक्ति को फोन कर 50 हजार रुपए मांगे। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में आकर पीड़ित ने आप बीती सुनाई। पीड़ित ने कहा, आपका बहुत नाम सुना है। जो दायरे में रहकर मकान बनाते हैं, उनको आप परेशान नहीं करते। फिर मुझसे कैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? फिर भी ईओ का ड्राइवर 50 हजार रुपए मांग रहा है। मैं लोन लेकर मकान बनवा रहा हूँ। पीड़ित ने लिखित शिकायत की।

जेडीए पहुंचे एक निर्माणकर्ता ने लगाया आरोप पुष्टि के बाद संबंधित चालक को हटाया

यह मामला पहला नहीं

राहुल जैन जेडीए में एसपी थे तब भी प्रवर्तन शाखा के ड्राइवरों पर उगाही के आरोप लगे थे। कई के बारे में तो पुष्टि भी हुई थी। इसके बाद जैन ने अधिकतर ड्राइवरों और उनके वाहनों को हटा दिया था। जुलाई में तो जून सात के ईओ को ऐसे ही एक मामले में उनके मूल विभाग भेज दिया गया था।

पहले आदर्शवाद की बातें कीं, फिर कबूल लिया

मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने ड्राइवर पवन को बुलाया और पूछा तो पवन ने कहा, मैंने किसी को फोन नहीं किया। मेरे परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि रिश्तत लूं। इसके बाद मुख्य नियंत्रक ने तथ्य रखे और मुकदमा

समझाइश बेकार

जेडीसी टी. रविकांत अपनी बैठकों में अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के काम शीघ्र और ईमानदारी से करने के निर्देश देते रहे हैं। 29 मई को तो उन्होंने फाइलों को जानबूझकर रोकने के मामले में 20 कर्मचारियों को नोटिस दिए थे। साथ ही एक कर्मचारी को निलम्बित किया।

दर्ज करवाने की चेतावनी दी तो पवन ने 50 हजार रुपए मांगने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पवन को नौकरी से हटा दिया गया। मामले की जांच डिप्टी एसपी कालूराम को सौंपी गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देंगे।